

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—इन्ड 3—उप-इन्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 394] No. 394] नई हिल्ली, शनिवार, सितम्बर 4, 1982/मात्र 13, 1904 NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 4, 1982/BHADRA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में उत्था जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औधोगिक विकास विभाग)

म्रादेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1982

का॰आ॰ 649(अ)/18एफ॰ए॰/18एए/आई॰डी॰ आर॰ए॰/82:-केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रौद्योभिक विकास मंद्रालय
के श्रादेश सं॰ का॰शा॰ 128(अ)/18 एफए/18कक/उ०वि०वि०अ०/73,
तारीख 5 मार्च, 1973 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को (जिसे इसमें
इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैससे कृष्णा सिलिकेट एण्ड
ग्लास वर्क्स लिमिटेड कलकता नामक श्रौद्योभिक उपकम का सम्पूर्ण
प्रबन्ध 5 मार्च, 1972 से पांच वर्ष की श्रवधि के लिये ग्रहण करने के
लिये प्राधिकृत किया था,

भौर केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (भौद्योगिक विकास विभाग) के भ्रादेश सं० का०भ्रा० 146(म्र)/18चक/18कक/उ०वि० वि०म्र०/78, तरिख मार्च, 1978, सं० का०भ्रा० 145(म्र)/18चक/18कक/उ०वि०वि०म्र०/80 तारीख 5 मार्च, 1980, सं० का०भ्रा० 144(म्र)/81, तारीख 4 मार्च, 1981, सं० का०भ्रा० 685 (म्र)/18चक/18कक/उ०वि०वि०म०/81, तारीख 4 सितम्बर, 1981 भौर सं०का०भ्रा० 12: (म्र)/18 एफ ए/18ए ए/म्राई०डी०मार०ए०/82 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति 675 GI/82

को उक्त भौद्योगिक उपक्रम का 4 सितम्बर, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सिम्मिलिति है, अतिरिक्त अविधि के लिये, प्रबन्ध करते रहने के लिये प्राधिकृत किया था,

ग्रीर केन्द्रिंय सरकार, ने श्रपनी यह राय होने पर कि सर्वसाधारण के हित में यह सभीचीन है कि प्राधिकत व्यक्ति उक्त ग्रीशोगिक उपक्रम क प्रबन्ध करना जारी रखें, उद्योग (विकास ग्रीर विनियमन) ग्रिधिनयमा 1951 (1951 का 65) की धारा 18चक की उपधारा (2) के परन्तुक के ग्रिधीन एक ग्रावेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय की किया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबन्ध एक वर्षकी ग्रीर प्रजीधे के लिये जारी रखा जाये,

श्रीर उक्त उक्क न्यायालय ने अपने तारीख 2 सितम्बर, 1982 के, आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त श्रीशोशिक उपक्रम का प्रबन्ध एक वर्ष की और अवधि तक नारी रखने के लिये अनुनात कर दिया था,

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 18कक के साथ पठित घारा 18चक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत व्यक्ति को निदेश देती है कि वह 5 मितम्बर, 1982 से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की ग्रीर अविध के लिए उक्त ग्रीधोगिक उपक्रम का प्रबन्ध करना जारी रखें।

> [फा०सं० 2(1)/80 के०००शु०] चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development) New Delhi, the 4th September, 1982

ORDER

S.O. 649(E)/18FA/18AA/IDRA\(^82.\)—Wherea\(^8\) by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 128(E)/18FA/18AA/IDRA/73, dated the 5th March, 1973, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973.

And whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 146(E)/18FA/18AA|IDRA|78, dated the 3rd March, 1978, No. S.O. 145(E)/18FA/18AA|IDRA|80, dated the 5th March, 1980, No. S.O. 144(E)/81, dated the 4th March, 1981, No. S.O. 685(E)/18FA/18AA|IDRA|81, dated the 4th September, 1981, and S.O. 123(E)|18FA|18AA/IDRA/82 dated the 4th March, 1982, the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for further periods upto and inclusive of 4th September, 1982.

And whereas the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of one year.

And whereas the said High Court, by its Order dated the 2nd September, 1982, permitted the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year.

And, now in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA, read with section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year commencing from the 5th September, 1982.

[F. No. 2(1)/80-Cus.]

C. K. MODI, Jt. Secy.